International Research Journal of Marketing & Economics
ISSN (2349-0314) Impact Factor: 6.618
Vol. 10, Issue 08, August 2023
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
Website-www.aarf.asia,Email id : editoraarf@gmail.com

प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत बुंदेलखंड के विकास और चुनौतियों का अध्ययन

डॉ0 मनोज कुमार मिश्र
प्रधानाचार्य, एस.पी.आई. इण्टर कॉलेज,
रानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने,
सिविल लाईन, झाँसी – 284001

उद्देश्य: *बुंदेलखंड, मध्य भारत का एक क्षेत्र, लंबे समय से गरीबी, अविकसितता और सामाजिक चुनौतियों से ग्रस्त है। भारत सरकार ने क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कई योजनाओं और पहलों को लागू किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता और उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की जांच करना है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा स्रोतों का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन प्रधान मंत्री योजनाओं के तहत बुंदेलखंड के विकास की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है । परिणाम बताते हैं कि जहां इन योजनाओं का कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वहीं अपर्याप्त धन, सामुदायिक भागीदारी की कमी और कमजोर कार्यान्वयन तंत्र जैसी चुनौतियों ने उनकी पूरी क्षमता को बाधित किया है। यह अध्ययन क्षेत्र की विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक नीतिगत ध्यान देने और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह बुंदेलखंड में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सिफारिशें भी प्रदान करता है। कुल मिलाकर, यह अध्ययन सरकार के नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से भारत में अल्पसेवित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने की चुनौतियों और अवसरों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।*

कीवर्ड: *बुंदेलखंड, प्रधानमंत्री की योजनाएं, विकास, चुनौतियां, गरीबी, सामुदायिक भागीदारी, कार्यान्वयन, नीतिगत ध्यान, सतत विकास, भारत।*

1. परिचय

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, हमारे देश ने सभी नागरिकों के लिए गरीबी और असमानता को खत्म करने के लिए काम किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक सीढ़ी के नीचे हैं। इसे हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में एक कदम आगे बढ़ाया गया है, जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास और सामाजिक निष्पक्षता दोनों है। हालांकि गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन सभी को विकास योजना के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का लाभ नहीं मिला है। पूरी कार्रवाई कम भाग्यशाली लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए की गई थी, और ऐसा करने के लिए और भी कार्यक्रम हैं।

गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभी भी विकासशील देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक है। जबकि पिछले दो दशकों में गरीबी की दर गिर रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबों की वास्तविक संख्या उसी के आसपास रह सकती है। लंबी अवधि में, गरीबी में कमी और त्वरित आर्थिक विकास रोजगार गहन योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग से लाभान्वित होंगे। बहरहाल, इस नीति के पूरक और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रित गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के रूप में राज्य की भागीदारी आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्व-रोज़गार और वेतन रोज़गार दोनों का निर्माण कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक केंद्रीय लक्ष्य है।

1.2 प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

शिक्षित बेरोजगारी के तत्काल मुद्दे को संबोधित करने के लिए, प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी। 1994-1995 से शुरू होकर, पीएमआरवाई ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए पिछले स्व-रोजगार (एसईईयूवाई) कार्यक्रम को अवशोषित किया। वाणिज्यिक, सेवा, या विनिर्माण क्षेत्रों में स्वयं की फर्म स्थापित करना PMRY के दायरे में आता है। वह व्यक्ति कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत मार्जिन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ऋणों के साथ, किसी संपार्श्विक या गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। चुकौती अवधि 6-18 महीने की छूट अवधि के बाद शुरू होती है और 3-9 साल तक चलती है। सरकार प्रति व्यवसाय स्वामी के लिए रु. 7,500 की सीमा के साथ, अधिकतम 1 लाख रु. तक की ऋण राशि के 15% की गारंटी देती है। एक संयुक्त उद्यम में अधिकतम पांच भागीदारों में से प्रत्येक को रु. 2 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। उद्यमिता विकास में योजना का अनिवार्य प्रशिक्षण उल्लेखनीय है। यह प्रशिक्षण एक माह के दौरान होगा। प्रशिक्षण के दौरान, इंटर्न को वेतन मिलता है। जिला स्तर पर, डीआईसी प्रणाली को एक मॉडल के रूप में लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पीएमआरवाई के विकास के लिए बैंक जैसे वित्तीय संस्थान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे युवा लोगों को ऋण प्रदान करते हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं।

2. साहित्य की समीक्षा

गीतिका, टंडन और कपूर, गीतिका (2023) भारत में, उत्तर प्रदेश राज्य में "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" (ODOP) नामक एक कार्यक्रम है जो विशिष्ट, स्थानीय और पारंपरिक सामानों को बढ़ावा देता है जो प्रत्येक राज्य के कई जिलों। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक वस्तुओं को वापस जीवन में लाया जाएगा, और स्थानीय कारीगरों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा यदि सरकार उन पर अधिक जोर देती है। उत्तर प्रदेश राज्य के 2018-2019 के बजट में इस पहल को लागू करने के उद्देश्य से $250,000,000 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय उत्पाद और हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए "एक जिला, एक उत्पाद" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह आलेख इस कार्यक्रम के राज्य के कार्यान्वयन द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम उत्पादन पद्धति और उत्पाद प्रकार का विश्लेषण करेगा। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उत्पादकों को ऋण सुविधा प्रावधान के मामले में योजना की दक्षता की भी जांच की जाएगी। सूचना के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं जो प्रभावित कर सकते हैं कि कार्यक्रम कैसे चलाया जाता है।

कुमार, सुरेश और माडेगौड़ा (2022) वाटरशेड पहलों के नियामक नियमों के आधार पर, यह शोध भारत में वाटरशेड के विकास को ट्रैक करता है। हम वाटरशेड नियमों के विकास का विश्लेषण करते हैं और इसे छह अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़े चरणों में विभाजित करते हैं। हमने पाया कि वाटरशेड सिफारिशों में भूमि क्षरण, आजीविका सुरक्षा, लिंग और सामाजिक न्याय, और जलवायु परिवर्तन शमन और प्रतिक्रियाओं की बढ़ती चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। हाल ही में, वाटरशेड ने सहायक संस्थागत संरचनाओं को बढ़ावा देना शुरू किया है जो उत्पादन-केंद्रित होने के बजाय आय-केंद्रित हैं। भारत के वाटरशेड कार्यक्रम समान पहलों पर विचार करते हुए अन्य विकासशील देशों के लिए सबक प्रदान करते हैं।

गुलाटी, अशोक और तेरवे , प्रेरणा और हुसैन, सिराज (2021) उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक (47%) लोग अपनी आय के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। जबकि टीई 2017-18 में कृषि का जीएसडीपी का प्रतिशत 12% तक गिर गया, यह अभी भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि यह कई लोगों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है।

शर्मा, पवन (2020) तेजी से आर्थिक विकास हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना जरूरी है। यह पूरे समुदायों को गरीबी से बाहर निकालने और दीर्घकालिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इस शोध का उद्देश्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 40 अलग-अलग ब्लॉकों के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के अंतराल की जांच करना था। अनुसंधान 2011 से कई सरकारी संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए माध्यमिक डेटा पर निर्भर करता है। ब्लॉक स्तर पर 12 मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक समग्र स्कोर की गणना की गई। अनुसंधान सूक्ष्म-क्षेत्रीय पैमाने पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अंतर को दर्शाता है, जिसमें नौगोंग ब्लॉक को 1.34 का उच्चतम स्कोर और बक्सवाहा ब्लॉक को -1.95 का सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ है। प्रिंसिपल कंपोनेंट

एनालिसिस ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर चार प्राथमिक प्रभाव दिखाए हैं। लोगों के रहने की स्थिति में सुधार लाने और सूक्ष्म क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए इन तत्वों से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जा सकता है।

बीएल, मंजूनाथा और राव, डी. और सिंह, रश्मी (2016) समाज शिल्पी दंपति वीएसआरसी की रीढ़ हैं; वे सामुदायिक सेवा के लिए एक मजबूत समर्पण के साथ नवविवाहित स्नातक जोड़े हैं जो गांवों में जाते हैं और स्थानीय लोगों के साथ पांच साल तक सेवा करते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए डीआरआई के प्रयासों की बात आती है, तो एसएसडी तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है । भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में परियोजना की अवधारणा, उत्पत्ति, प्रक्रिया और संचालन की इस जांच का उद्देश्य वहां के लोगों की आजीविका पर इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव की जांच करना था। एसएसडी को पांच पड़ोसी समुदायों के समूह द्वारा नियोजित किया जाता है और उनका अपना समुदाय होता है। SSD इकाई पाँच पड़ोसी समुदायों का एक संग्रह है । प्रत्येक SSD के पास एक यादच्छिक गाँव होता है जिसे उसमें से चुना जाता है। प्रत्येक समुदाय से 20 कृषक परिवारों को यादच्छिक रूप से चुना गया। जानकारी के लिए एक सौ ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। पांच एसएसडी (10 पदाधिकारियों) और डीआरआई की विभिन्न संस्थाओं के बीस अधिकारियों से भी प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। शोध में कुल मिलाकर 130 प्रतिभागी थे । SSDs, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सफलता के लिए मजबूत ड्राइव, व्यवसाय के प्रति वफादारी, अपने साथी मनुष्यों में विश्वास, स्वायत्तता की इच्छा, और प्रगति और विकास की ओर एक नजर पाए गए। योजना का इसके प्रतिभागियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिन्होंने आय, बचत और काम के घंटों में वृद्धि देखी। अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने परिवार के लिए साल भर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1.5 से 2.5 एकड़ की योजना का उपयोग किया; यह सीमांत और छोटे खेतों के बीच विशेष रूप से सच था।

3. कार्यप्रणाली

एक शोध परियोजना की तकनीक महत्वपूर्ण है। तकनीक वह दृष्टिकोण है जिसका उपयोग शोधकर्ता द्वारा जांच के दौरान वास्तव में क्या हुआ, इसकी तह तक जाने के लिए किया जाता है, इसके विपरीत कि शोधकर्ता क्या करना चाहता था। अर्थव्यवस्था लोगों के कार्यों से प्रभावित होती है, जो समय और भूगोल के माध्यम से बदल सकती है।

3.1 आंकड़ों का संग्रह

इस शोध के लिए आँकड़ों को संकलित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा एक आजमाए हुए और सच्चे साक्षात्कार दिनचर्या का उपयोग करके नमूना प्राप्तकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार आयोजित करने से आया है । इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सर्वेक्षण शुरू होने से पहले ड्राफ्ट साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके तीस प्राप्तकर्ताओं का साक्षात्कार लिया गया था। गैर-जवाब और अनावश्यक प्रश्नों के उन्मूलन में व्यक्ति ने सहायता की और इस जानकारी के आधार पर अंतिम अनुसूची को संशोधित किया गया।

3.2 अध्ययन के उद्देश्य

- कार्यक्रम के उपयोग का अध्ययन करने के लिए और यह जानने के लिए कि प्राप्तकर्ता अपने घरों में कितना पैसा ला रहे हैं
- PMRY योजना से परिणामी आय, संपत्ति और नौकरियों की जांच करना।

4. परिणाम और चर्चा

4.1 अध्ययन की रूपरेखा

4.1.1 आयु

नमूना प्राप्तकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी आयु है। अपने संबंधित क्षेत्रों में, एक निश्चित आयु के लोगों में अधिक विशेषज्ञता होती है। तालिका 4.1 अध्ययन के प्रतिभागियों का चार आयु वर्ग में विभाजन प्रदान करती है: 30 से कम, 30 और 40 के बीच, 40 और 50 के बीच, और वे 50 और उससे अधिक।

तालिका 4.1 नमूना लाभार्थियों का आयु वर्गीकरण

क्र.सं. नहीं।	आयु	उद्यम			कुल
		व्यवसाय	उद्योग	सेवा	
1.	20 -3 0	26 (10.88)	5 (15.16)	14 (10.93)	45 (11.25)
2.	30 - 40	123 (51.46)	13 (39.39)	62 (48.44)	198 (49.50)
3.	40 - 50	61 (25.52)	8 (24.24)	31 (24.22)	100 (25.00)
4.	50 और ऊपर दिए गए	29 (12.14)	7 (21.21)	21 (16.41)	57 (14.25)
	कुल	239 (100.00)	33 (100.00)	128 (100.00)	400 (100.00)

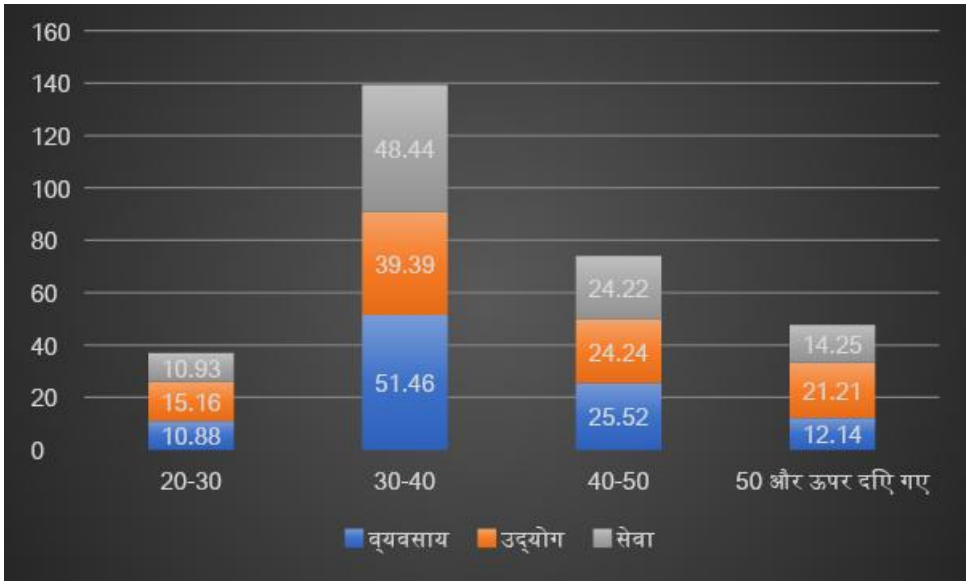

चित्र 4.1 नमूना लाभार्थियों का आयु वर्गीकरण

व्यापार उद्यम के तहत 239 नमूना लाभार्थियों की तालिका 4.1 से, सबसे बड़ा अनुपात (123, या 51.46 प्रतिशत) 30 और 40 की उम्र के बीच है, इसके बाद 61, या 25.52 प्रतिशत, 29, या 12.14 प्रतिशत, और शेष 26, या 10.88 प्रतिशत, जिनकी उम्र 50 या उससे अधिक है। औद्योगिक समूह में 33 नमूना लाभार्थियों में से, 13.3 प्रतिशत 30 और 40 वर्ष की आयु के बीच हैं, इसके बाद 24.2 प्रतिशत 40 और 50 वर्ष की आयु के बीच, 21.2 प्रतिशत 50 और उससे अधिक आयु के बीच, और 15.16 प्रतिशत आयु के बीच हैं 20 और 30।

4.1.2 शिक्षा

एक अच्छी शिक्षा मन और हृदय दोनों को व्यापक बनाती है। परिणामस्वरूप स्थिति को समझने की क्षमता में सुधार होता है। एक शिक्षित व्यक्ति के नई परिस्थितियों में सफल होने, अधिक सार्थक बातचीत करने और दूसरों को अपनी बातों से मनाने की संभावना अधिक होती है। तालिका 4.2 शिक्षा के स्तर के आधार पर नमूने के लाभार्थियों के वितरण को तीन

समूहों में विभाजित करती है : हाई स्कूल डिप्लोमा या उससे कम, कॉलेज डिग्री और तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले।

तालिका 4.2 नमूना लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति

क्र.सं. नहीं।	शिक्षात्मक दर्जा	उद्यम			कुल
		व्यवसाय	उद्योग	सेवा	
1.	तक एसएसएलसी/ एचएससी	171 (71.55)	19 (57.58)	93 (72.66)	283 (70.75)
2.	स्नातक और डाक	41	10	11	62
	स्नातक	(17.15)	(30.30)	(8.59)	(15.50)
3.	तकनीकी शिक्षा / पेशेवर शिक्षा	27 (11.30)	4 (12.12)	24 (18.75)	55 (13.75)
	कुल	239 (100.00)	33 (100.00)	128 (100.00)	400 (100.00)

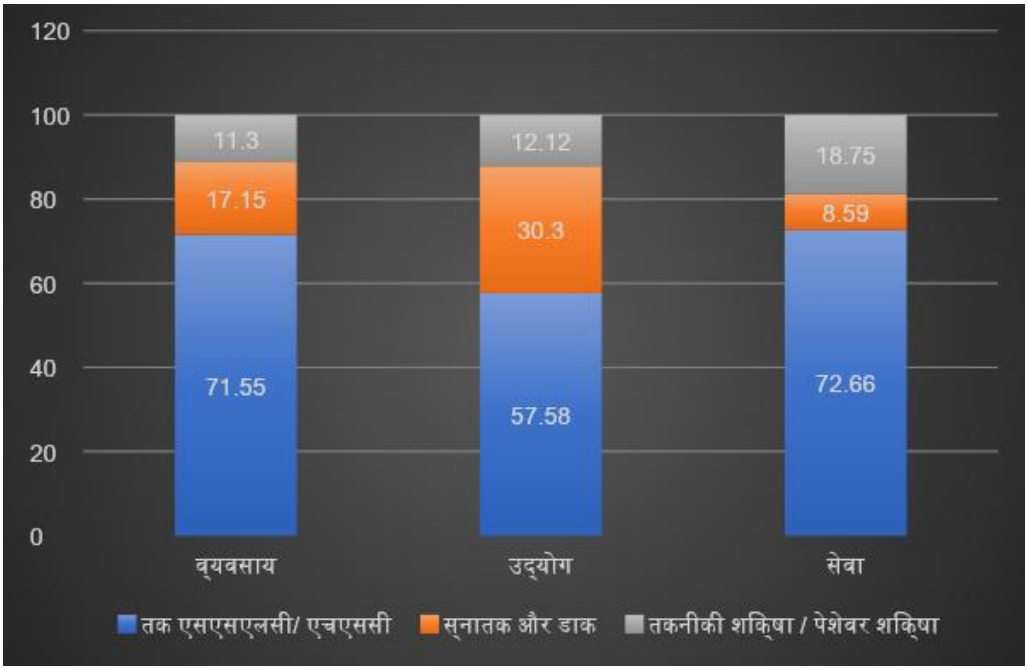

चित्र 4.2 नमूना लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति

तालिका 4.2 के आंकड़ों के अनुसार, व्यावसायिक उद्यम (71.55 प्रतिशत) की श्रेणी में 239 नमूना लाभार्थियों में से अधिकांश ने केवल माध्यमिक विद्यालय (एसएससी) या उच्चतर (एचएससी) के माध्यम से पूरा किया है, जबकि 17.15 प्रतिशत कॉलेज स्नातक या स्नातकोत्तर हैं और 11.30 प्रतिशत तकनीकी रूप से योग्य हैं (डिप्लोमा धारक, आईटीआई प्रमाणपत्र धारक, या पेशेवर)।

4.2 सूचना के स्रोत और पीएमआरवाई योजना का प्रदर्शन

इस खंड में, हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि बुंदेलखंड जिले में कितने लोगों ने पीएमआरवाई कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण लिया है।

4. 2.1 योजना के बारे में जानकारी का स्रोत

नमूना प्राप्तकर्ता अपने सूचना स्रोतों की विश्वसनीयता पर प्रीमियम लगाते हैं। इस अध्ययन में, शोधकर्ता ने कार्यक्रम के बारे में ज्ञान के स्रोत पर विचार किया है, क्योंकि इसके बिना लाभार्थी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तालिका 4.3 कई श्रेणियों को प्रदर्शित करती है जिसमें "मित्र/रिश्तेदार," "समाचार पत्र और विज्ञापन," "सरकारी एजेंसियां," "रेडियो/टीवी," और "स्वैच्छिक संगठन" शामिल हैं।

तालिका 4.3 योजना के बारे में सूचना के स्रोत

क्र.सं. नहीं।	स्रोत	उद्यम			कुल
		व्यवसाय	उद्योग	सेवा	
1.	दोस्त/ सगे-संबंधी	98 (41.00)	11 (33.33)	51 (39.84)	160 (40.00)
2.	अखबार और विज्ञापनों	34 (14.23)	8 (24.24)	35 (27.34)	77 (19.25)
3.	सरकार अधिकारियों	37 (15.48)	7 (21.22)	28 (21.88)	72 (18.00)
4.	रेडियो / टीवी	59 (24.69)	5 (15.15)	11 (8.59)	75 (18.75)
5.	स्वैच्छिक संगठन	11 (4.60)	2 (6.06)	3 (2.35)	16 (4.00)
	कुल	239 (100.00)	33 (100.00)	128 (100.00)	400 (100.00)

तालिका 4.3 में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यावसायिक उद्यम (98, या 41%) के तहत 239 नमूना लाभार्थियों में से अधिकांश व्यक्तिगत कनेक्शन से अवसरों के बारे में सीखते हैं, इसके बाद 59 (24.69%), 37 (15.48%) आते हैं।), 34 (14.23%), और 11 (4.60%), जो क्रमशः सरकारी अधिकारियों, समाचार पत्रों और विज्ञापनों और गैर-लाभकारी संस्थाओं से अवसरों के बारे में सीखते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 33 लाभार्थियों में से 11 (33.33%) ने इसके बारे में व्यक्तिगत संपर्क से सीखा, 7 (21.22%) ने सरकारी अधिकारियों से इसके बारे में सीखा, 5 (15.15%) ने इसके बारे में रेडियो/टीवी प्रसारण से सीखा, और 2 (6.06%) ने इसके बारे में गैर-लाभकारी संगठनों से सीखा। इस अध्ययन के लिए चुने गए 128 लाभार्थियों में से 39.8 प्रतिशत ने व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में सीखा, 27.3 प्रतिशत ने इसके बारे में मीडिया और विज्ञापन के माध्यम से सीखा, 21.8 प्रतिशत ने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से इसके बारे में सीखा, 8.5 प्रतिशत ने इसके बारे में रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सीखा, और 2.3 प्रतिशत ने इसके बारे में एक गैर-लाभकारी संगठन के माध्यम से सीखा ।

4.2.2 पीएमआरवाई को चुनने के कारण

कुछ भी करने के हमेशा अच्छे कारण होते हैं। वर्तमान शोध ने उन कारकों को उजागर किया है जिन्होंने प्रतिभागियों को पीएमआरवाई कार्यक्रम चुनने के लिए प्रेरित किया। पीएमआरवाई योजना को चुनने के लिए निम्नलिखित औचित्य को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: तालिका 4.4 कारकों के प्रभाव का विवरण देती है जैसे नौकरी की संभावनाओं की कमी, किसी की क्षमताओं का उपयोग करने का मौका, किसी के पिछले काम की लाभप्रदता, सरकारी सब्सिडी का आकर्षण, और अन्य व्यापार मालिकों का समर्थन।

तालिका 4. PMRY को चुनने के 4 कारण

क्र.सं. नहीं।	कारण	उद्यम			कुल
		व्यवसाय	उद्योग	सेवा	
1.	कमी का रोज़गार अवसर	126 (52.72)	6 (18.18)	54 (42.19)	186 (46.50)
2.	स्वयं के उपयोग का अवसर कौशल	10 (4.18)	9 (27.27)	59 (46.09)	78 (19.50)
3.	पिछले रोजगार नहीं लाभदायक	65 (27.20)	11 (33.34)	11 (8.59)	87 (21.75)
4.	का आकर्षण सरकार सब्सिडी	38 (15.90)	3 (9.09)	4 (3.13)	45 (11.25)
5.	प्रोत्साहन दिया द्वारा अन्य उद्यमियों	-	4 (12.12)	-	4 (1.00)
	कुल	239 (100.00)	33 (100.00)	128 (100.00)	400 (100.00)

तालिका 4.4 से पता चलता है कि व्यावसायिक उद्यमों में 239 नमूना लाभार्थियों में से अधिकांश 126 (52.72%) का कहना है कि पीएमआरवाई योजना को चुनने का प्राथमिक कारण रोजगार के अवसर की कमी है, जबकि शेष 10 (14.18%) का कहना है कि इसके लिए कारण पीएमआरवाई योजना का चयन करने वाले हैं कि पिछला रोजगार लाभदायक नहीं था, सरकारी सब्सिडी का आकर्षण और खुद के कौशल का उपयोग करने का अवसर, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि रोजगार के अवसर की कमी एक कारक थी। उद्योग उद्यम में नमूना लाभार्थियों के अधिकतम 11 (33.34%) पिछले रोजगार के लाभदायक नहीं होने के कारण बताते हैं, इसके बाद 9 (27.27%), 6 (18.18%), 4 (12.12%), और शेष 3 (9.09) %), जो किसी के कौशल का उपयोग करने का अवसर, उपलब्ध नौकरियों की कमी, साथी व्यवसाय मालिकों का समर्थन और सरकारी सब्सिडी की अपील जैसे कारकों का हवाला देते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 128 लाभार्थियों में से 46.9% ने अपने कौशल का उपयोग करने का मौका दिया, इसके बाद 42.19% ने रोजगार के अवसरों की कमी का हवाला दिया, 8.59% ने अपनी पिछली नौकरी में लाभप्रदता की कमी का हवाला दिया, और 3.13 सरकारी सब्सिडी के आकर्षण का हवाला देते हुए%। हालांकि, किसी भी उत्तरदाता ने प्रेरक कारक के रूप में अन्य व्यापार मालिकों से प्राप्त समर्थन का हवाला नहीं दिया।

4.2.3 वर्तमान उद्यम के चयन के कारण

इस जांच में, शोधकर्ता ने विचार किया है कि लाभार्थियों ने इस विशेष उद्यम को क्यों चुना है । तालिका 4.5 निर्णय लेने के मानदंड का विवरण देती है, जिसके कारण वर्तमान उद्यम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें उत्पाद के लिए बाजार की मांग, प्रासंगिक कार्य अनुभव, स्थान से संबंधित विचार, पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार करने की इच्छा, प्रासंगिक प्रशिक्षण का प्रभाव और आवश्यकता शामिल है। एक बड़ी ऋण राशि के लिए।

तालिका 4. वर्तमान उद्यम को चुनने के 5 कारण

क्र.सं. नहीं।	**कारण**				**कुल**
		व्यवसाय	**उद्योग**	**सेवा**	
1.	माँग के लिए उत्पाद	52 (21.76)	11 (33.33)	67 (52.34)	130 (32.50)
2.	पहले का अनुभव	57 (23.84)	9 (27.28)	26 (20.31)	92 (23.00)
3.	का प्रभाव स्थानीय कारकों	122 (51.05)	6 (18.18)	22 (17.19)	150 (37.50)
4.	परिवार व्यवसाय	-	4	-	4
	विस्तार		(12.12)		(1.00)
5.	प्रभाव का प्रशिक्षण program' उपस्थित हुए	-	3 (9.09)	13 (10.16)	16 (4.00)
6.	अधिकतम ऋण राशि का लाभ उठाने की इच्छा	**8** **(3.35)**	-	-	8 (2.00)
	कुल	**239**	33	128	400
		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

तालिका 4.5 से पता चलता है कि, 239 नमूना लाभार्थियों में से, जो अधिकतम व्यापार उद्यम के अंतर्गत आते हैं, 51.05 प्रतिशत ने स्थान के प्रभाव के कारण अपने उद्यम को चुना, इसके बाद 23.84 प्रतिशत, 21.76 प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत ने अपने उद्यम को पूर्व अनुभव के कारण चुना। उत्पाद की मांग, और अधिकतम ऋण राशि निकालने की इच्छा। अध्ययन के नमूने से लाभान्वित होने वाले 33 लोगों में से 11 (33.33%) ने उत्पाद के लिए उपभोक्ता मांग के कारण उद्योग में प्रवेश करना चुना, जबकि अन्य 9 (27.28%), 6 (18.18%), 4 (12.12%), और 3 (9.09%) ने पूर्व अनुभव, स्थान के प्रभाव और उद्योग में प्रवेश करने के कारणों के रूप में पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार करने की इच्छा का हवाला दिया। फिर भी, किसी ने भी अपना व्यवसाय नहीं चुना है क्योंकि वे सबसे बड़ा संभावित ऋण लेना चाहते थे। सर्वेक्षण किए गए 128 लाभार्थियों में से 67 (52.34 प्रतिशत) बाजार की मांग के कारण अपना सेवा उद्यम चुन रहे हैं। अन्य 26 (20.31 प्रतिशत),

22 (17.19 प्रतिशत), और 13 (10.16 प्रतिशत) पूर्व अनुभव, स्थानीय कारकों के प्रभाव, और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनकी प्रेरणा के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का हवाला देते हैं। लेकिन, पारिवारिक फर्म के विस्तार के कारण किसी को भी अपने उद्यम के लिए पूरी ऋण राशि नहीं मिली है।

5. निष्कर्ष

भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष 16 मिलियन की चौंका देने वाली गति से बढ़ रही है, जो पृथ्वी पर किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। देश की जनसंख्या आकार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हर साल, भारत की जनसंख्या वृद्धि एक और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने के बराबर है। हर इंसान दो कामकाजी हाथों और एक मुंह के साथ पैदा होता है। पीएमआरवाई कार्यक्रमों के समान , आगे की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ आगे के रोजगार कार्यक्रम स्थापित किए जाएंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में, पीएमआरवाई पहल ने साक्षर और अशिक्षित युवाओं, जो अन्यथा बेरोजगार हैं, दोनों के लिए रोजगार सृजित किया है। लाभार्थियों की संपत्ति की स्थापना से राजस्व में वृद्धि ने लोगों को योजना के लिए धन्यवाद देने में मदद की है। इसके अलावा, योजना ने कई स्थानीय महिला व्यापार मालिकों को लाभकारी काम खोजने में मदद की। अन्य तालुकों की तुलना में, बुंदेलखंड उत्तर में पीएमआरवाई योजना को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन और परिणाम हैं।

संदर्भ

1. गीतिका, टंडन और कपूर, गीतिका। (2023)। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी कार्यक्रम के तहत उत्पादन पैटर्न और ऋण में आसानी का अध्ययन।
2. कुमार, सुरेश और मडेगौड़ा, मधु और मोंडल, बिस्वजीत और कुमार, अशोक। (2022)। वाटरशेड दिशानिर्देशों का उपयोग करके भारत में वाटरशेड विकास के प्रक्षेपवक्र का पता लगाना: नीतिगत अंतर्दृष्टि। वर्तमान विज्ञान। 125. 968-974। 10.18520/सीएस/वी123/आई8/968-974.
3. गुलाटी, अशोक और तेरवे , प्रेरणा और हुसैन, सिराज। (2021)। उत्तर प्रदेश में कृषि का प्रदर्शन। 10.1007/978-981-15-9335-2_7.
4. शर्मा, पवन. (2020)। बुंदेलखंड क्षेत्र में ढांचागत विकास: एक सूक्ष्म-स्तरीय विश्लेषण। 16. 1-15।
5. बीएल, मंजूनाथ और राव, डी. और सिंह, रश्मी। (2016)। एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए एक अभिनव विस्तार मॉडल: समाज शिल्पी दम्पती योजना का एक मामला। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। 52. 177-182।
6. हरिहरन, एनपी लाइट्स एंड शेड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विशाल पब्लिशिंग कंपनी, जालंधर 2005।
7. चटर्जी: भारत में विकास रोजगार कार्यक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था, Vol.XVI , दिसंबर 2003। परमेश्वर गुप्ता, ईए सैयद रहमतुल्ला और एसएल शंकर , "माइक्रोफाइनेंस का प्रभाव: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण" दक्षिणी अर्थशास्त्री, Vol.48, No.18 , 15 जनवरी 2010।
8. मनोहर आर. और के. उथिरा , "माइक्रो क्रेडिट - ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक रामबाण", किसान वर्ल्ड, वॉल्यूम 34, नंबर 11, नवंबर 2007।
9. कृष्णमूर्ति एस. और पी. अलगरसामी , बैंक क्रेडिट टू एसएसआई सेक्टर: ए केस स्टडी, सदर्न इकोनॉमिस्ट, 1 मार्च, 2013।
10. कोमला के., केवी एलियाना और चिक्कारंगास्वामी , "SHG's as an Instrument for Women, Empowerment", सदर्न इकोनॉमिस्ट, Vol.48, No.17, 1 जनवरी, 2011।